



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 140

दि. 22.02.2026,

रविवार

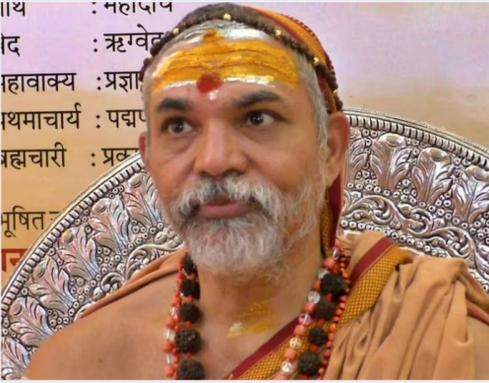
पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर का आदेश, यौन शोषण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

(जीएनएस)। प्रयागराज में स्थित एडीजे (रेप एवं पॉक्सो) स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप किया है। अदालत ने झूठी शाना पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिवत जांच शुरू की जाए। इस आदेश के बाद धार्मिक और सामाजिक जगत में हलचल तेज हो गई है और यह मामला व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि उपलब्ध तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों

के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने और विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब झूठी शाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह मामला तब सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को अदालत में एक अर्जी दायर की थी। यह अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में



नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत

को इस संबंध में एक सीडी भी सौंपने का दावा किया, जिसमें कथित तौर पर संबंधित घटनाओं से जुड़े साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पीड़ितों के बयान सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दर्ज हों, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। बयान दर्ज करने और पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्टों की संज्ञान लेने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अदालत ने अब एफआईआर दर्ज करने

का औपचारिक आदेश जारी किया है। यह आदेश इस बात का संकेत है कि अदालत ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और मामले की निष्पक्ष जांच को आवश्यक माना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने घोषणा की कि वह प्रयागराज से चारणसी स्थित विद्या मठ तक 'सनातन यात्रा' निकालेंगे, जिसका उद्देश्य लोगों के सामने कथित सच्चाई को लाना है। उनका आरोप है कि विद्या मठ में ही नाबालिग बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं हुई थीं। इस मामले के सामने आने के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग इसे एक गंभीर मामला

मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक संवेदनशील धार्मिक मुद्दा बताते हुए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की विस्तृत जांच करेगी, जिसमें आरोपियों से पूछताछ, साक्ष्यों की जांच और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करना शामिल होगा। जांच के आधार पर पुलिस अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आरोप साबित होते हैं, तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक प्रमुख धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष और

पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक होती है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। पुलिस का मुख्य उद्देश्य मामले की निष्पक्ष जांच करना और सच्चाई को सामने लाना होगा। इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच निष्पक्ष और कानूनी तरीके से की जाएगी।

सूरत के चर्चित बिल्डर तुषार घेलानी सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, महिला मित्र हिरासत में, पुलिस जांच से सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

(जीएनएस)। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी से उभर रहे सूरत शहर में हुए चर्चित बिल्डर तुषार घेलानी आत्महत्या मामले ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में उभर पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए घेलानी की महिला मित्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद शहर के रियल एस्टेट जगत, कारोबारी समुदाय और आम नागरिकों के बीच इस मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस की तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट संकेत मिले हैं कि लगातार मानसिक दबाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों ने इस दुखद घटना को जन्म दिया। यह मामला 1 फरवरी 2026 को उस समय सामने आया था, जब शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर तुषार घेलानी ने अपने ही घर में अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। घटना के तुरंत बाद परिवार और परिचितों में हड़कंप मच गया था और उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी गंभीर चोट के कारण उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी रही। लगभग पांच दिनों तक जीवित और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। यह खबर पूरे शहर के लिए एक गहरा सदमा थी, क्योंकि तुषार घेलानी न केवल एक सफल बिल्डर थे, बल्कि समाज में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित



व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते थे। घटना के बाद से ही परिवार के सदस्यों ने इस आत्महत्या के पीछे उनकी महिला मित्र की भूमिका होने का आरोप लगाया था। परिवार का कहना था कि पिछले कुछ समय से तुषार घेलानी मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव से गुजर रहे थे और इसके पीछे उनकी महिला मित्र के साथ चल रहा विवाद प्रमुख कारण था। हालांकि शुरुआत में मामला काफी जटिल और पेचीदा नजर आ रहा था, क्योंकि आरोपी महिला ने भी अपनी ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे जांच और अधिक संवेदनशील और जटिल हो गई थी। उभर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अत्यंत सावधानी और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जांच शुरू की। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिपोर्टें, मोबाइल मैसेज, सोशल मीडिया गतिविधियों, डिजिटल फुटप्रिंट्स और वित्तीय लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घटनाओं की पूरी श्रृंखला को समझने का प्रयास किया।

जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिन्होंने मामले की दिशा बदल दी। जांच का नेतृत्व कर रहे एसीपी Z. R. Desai ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि महिला मित्र द्वारा लगातार बनाए गए मानसिक दबाव और व्यक्तिगत तनाव ने तुषार घेलानी को अत्यंत कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि इन साक्ष्यों के आधार पर महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से संबंधों में तनाव चल रहा था और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। कॉल रिपोर्टों और मैसेज के विश्लेषण से यह संकेत मिला कि तुषार घेलानी मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान थे। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या किसी और ने भी इस मानसिक दबाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।

सूरत में टेक्सटाइल क्रांति की शुरुआत: SITEX 2026 में दुनिया की पहली फोर-ब्लेड हाई-स्पीड जैक्वार्ड मशीन लॉन्च, उद्योग को मिलेगी नई वैश्विक पहचान

(जीएनएस)। देश की टेक्सटाइल राजधानी के रूप में पहचान बना चुका सूरत एक बार फिर तकनीकी नवाचार और औद्योगिक प्रगति का केंद्र बन गया है। शहर में आयोजित SITEX – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ अत्यंत उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण के बीच हुआ, जिसने न केवल दक्षिण गुजरात बल्कि पूरे देश के टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा देने का संकेत दिया है। यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन हॉल कन्वेंशन सेंटर, सरसाना में आयोजित की गई है, जहाँ देशभर से आए उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ, मशीन निर्माता और निर्यातक एक मंच पर एकत्र हुए हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य आधुनिक टेक्सटाइल मशीनरी और नई तकनीकों को उद्योग से जोड़कर उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इस आयोजन का संचालन Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry और सरदर गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा किया गया है, जिसने इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण टेक्सटाइल मशीनरी आयोजनों में शामिल कर दिया है। SITEX का कई गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा हाई-स्पीड एयरजेट मशीन का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसने यह दिखाया कि कैसे आधुनिक तकनीक को माध्यम से कम समय में अधिक उत्पादन संभव है। इन मशीनों के माध्यम से उद्योगपतियों को लागत कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने और



तकनीक, एम्ब्रॉयडरी इक्विपमेंट और संकुलर निटिंग मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे उद्योग से जुड़े लोगों को भविष्य की तकनीकी दिशा का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया की पहली फोर-ब्लेड हाई-स्पीड रैपियर जैक्वार्ड मशीन का लॉन्च रहा, जिसने टेक्सटाइल उद्योग में एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत कर दी है। यह मशीन अत्यधिक गति और सटीकता के साथ जटिल डिजाइन वाले फैब्रिक का उत्पादन करने में सक्षम है, जिससे उत्पादन की गति कई गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा हाई-स्पीड एयरजेट मशीन का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसने यह दिखाया कि कैसे आधुनिक तकनीक को माध्यम से कम समय में अधिक उत्पादन संभव है। इन मशीनों के माध्यम से उद्योगपतियों को लागत कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने और

व्यापारियों ने भी इस आयोजन को टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उनका मानना है कि नई मशीनरी और तकनीक के उपयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सूरत के उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। कई उद्योगपतियों ने नई मशीनों में निवेश की योजना बनाई है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदर्शनी में प्रदर्शित मशीनों में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बन सके। सूरत लंबे समय से सिंथेटिक फैब्रिक, साड़ी और ड्रेस मटेरियल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब तकनीकी नवाचार के माध्यम से यह शहर वैश्विक टेक्सटाइल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। SITEX 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सूरत का उद्योग केवल पारंपरिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। इस प्रदर्शनी ने उद्योग, निवेश और तकनीकी विकास के नए द्वार खोल दिए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में सूरत न केवल भारत बल्कि विश्व के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरपंचों को प्रशासक बनाने का ऐतिहासिक निर्णय

(जीएनएस)। राज्य के ग्रामीण प्रशासन को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया है। जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या 28 फरवरी तक समाप्त होने वाला है, वहां वर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के माध्यम से इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों, विकास योजनाओं और जनसेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की निरंतरता बनी रहे। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य की अनेक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कारणों से पंचायत चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो सके हैं। इस स्थिति में प्रशासनिक शून्यता उत्पन्न होने की संभावना थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और दैनिक प्रशासन प्रभावित हो सकता था। सरकार ने इस संभावित संकट को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारिक और त्वरित समाधान अपनाया है, जिससे पंचायतों की कार्यप्रणाली में निरंतरता बनी रह सके। जारी सर्कुलर के अनुसार, मौजूदा सरपंचों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक छह महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। यदि इस अवधि के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार इस कार्यकाल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होंगे और नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, प्रशासक के रूप में नियुक्त सरपंच का कार्यकाल



स्वतः समाप्त हो जाएगा और नई पंचायत अपने अधिकारों के साथ कार्यभार संभाल लेगी। इस व्यवस्था से प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जिले में संबंधित जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन ग्राम पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाना है और उनकी नियुक्ति विधिवत तरीके से की जाए। यह व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार ने केवल सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पंचायतों के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक प्रशासनिक समिति के गठन की भी प्रारंभिक योजना है। इस समिति में उपसरपंच और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य शामिल होंगे। यह समिति प्रशासक के साथ मिलकर पंचायत के नियमित कार्यों का संचालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी

कि विकास योजनाएं, सरकारी परियोजनाएं और जनकल्याण कार्यक्रम विना किसी बाधा के जारी रहें। इस समिति को संबंधित कानूनों और नियमों के तहत आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिससे वे पंचायत के हित में निर्णय ले सकें और आवश्यक निर्देश जारी कर सकें। इस निर्णय के पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी न पड़े और जनता को किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्राम पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती हैं और इनके माध्यम से ही सरकार की अधिकारी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं। यदि पंचायतों में प्रशासनिक रिक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ता है। इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था निरंतर बनी रहे और जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। कई सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने इस फैसले को व्यावहारिक और आवश्यक कदम बताया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और पंचायत स्तर पर चल रही योजनाएं बाधित नहीं होंगी। इसके साथ ही ग्रामीण नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि, इस फैसले के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber, Jio tv+, Jio Fiber, Daily Hunt, ebaba Tv, Dish Plus, DTH live OTT, Rock TV, Airtel, Amezone Fire, Roku, Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

राजकोट का शहरी विकास 'ईज ऑफ लिविंग' के विजन को चरितार्थ कर रहा है

आगामी समय में राजकोट के लोगों को मिलेगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, आवास, फिल्टर प्लांट और लायन सफारी की सौगात

जीएनएस)। गांधीनगर : 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य के महत्वपूर्ण शहर राजकोट में भी आगामी समय में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजकोट महानगर पालिका की ओर से शहर में आवास, पुल और सड़कों सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते आगामी दिनों में राजकोटवासियों को नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिल्टर प्लांट और लायन सफारी पार्क जैसी सुविधाओं की सौगात मिलेगी।

राजकोट को मिलेगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और किरायाती आवास की सुविधाएँ
गुजरात सरकार के शहरी विकास वर्ष



2025 के अंतर्गत राजकोट महानगर पालिका की ओर से वार्ड नं. 17 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। ओलिंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखते हुए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजाइन और सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार होने के बाद राजकोट सहित सौराष्ट्र के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध होगा। नागरिकों को किरायाती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राजकोट महानगर पालिका की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 119 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रेल नगर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - 2 श्रेणी के 1010 आवासों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। आवास योजना में रूफटॉप सोलर सिस्टम, पानी की लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, गैस पाइप लाइन, ऑटो डोर लिफ्ट, वर्षा जल संचयन, ऑटो डीजी जनरेटर सेट्स, फायर टैंक और फुलप्रूफ फायर सिस्टम तथा बच्चों के खेलने के मैदान जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इस आवास योजना को इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी एकीकृत और समावेशी तरीके से प्लान किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी और शॉपिंग सेंटर की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक वर्किंग विमेन हॉस्टल राजकोट शहर सौराष्ट्र का औद्योगिक हब

भी है। ऑटो इंजीनियरिंग सहित अनेक क्षेत्रों में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजकोट में आगामी समय में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ग्रांट आवंटित की गई है। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में अत्याधुनिक वर्किंग विमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 49 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस हॉस्टल का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है।

फिल्टर प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की सुविधाएँ

राजकोट के विस्तार के साथ-साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए न्यारो में 50 एमएलडी (दस लाख लीटर प्रतिदिन) क्षमता वाला फिल्टर प्लांट बनाने का आयोजन किया गया है। इसके लिए इस क्षेत्र में 342.72 लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड सम्प (भूमिगत भंडारण

सुविधा) तथा पम्प हाउस का कार्य जारी है। इसके अलावा, माध्याह्न क्षेत्र में 31.75 करोड़ रुपये के खर्च से 24.19 एमएल (मिलियन लीटर) क्षमता का ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर (भूमि पर जल भंडारण के लिए टंकी) और 3 एमएल क्षमता के एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ऊँचाई पर पानी की टंकी) की सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं और पम्पिंग स्टेशन का कार्य जारी है।

लायन सफारी पार्क बनने का आकर्षण का केंद्र

शहर के पर्यटन विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर राजकोट महानगर पालिका लायन सफारी पार्क प्रोजेक्ट के काम को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। लायन सफारी पार्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक कंपाउंड वॉल (परिसर की दीवार), जानवरों और आगंतुकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 5 मीटर ऊँची चैन लिंक फेंसिंग

दीवार (बाड़) का काम, जानवरों के लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से नाइट शेल्टर, पार्क के अंदरूनी क्षेत्र में आसान आवाजाही के लिए आंतरिक सड़कें बनाने का काम तथा पार्क क्षेत्र के बाहर इन्फेक्शन रोड का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। आगामी दिनों में लायन सफारी पार्क शहर के लोगों के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र बनेगा।

राज्य सरकार ने राजकोट शहर को भी अधिक उन्नत बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। अटल सरोवर, अखिल भारतीय आर्युर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और कई फ्लाइंगोवर सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से राजकोट का कायापालट हुआ है और शहरीजनों की सुख-सुविधा में वृद्धि हुई है। ये सभी विकास कार्य शहरीजनों की खुशहाली बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

अहमदाबाद मंडल में दिसंबर 2025 से 19 फरवरी 2026 तक 484 अलार्म चैन पुलिंग की घटनाएँ दर्ज

449 मामलों में केस दर्ज तथा 48700 का वसूला जुर्माना

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में दिसंबर 2025 से 19 फरवरी 2026 के बीच कुल 484 अलार्म चैन पुलिंग (ACP) की घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें से 449 मामलों में विधिवत केस दर्ज किए गए, जबकि शेष मामलों में प्रारंभिक जांच के उपरान्त वैधानिक कारणों से केस दर्ज नहीं किया गया। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा 408 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 48,700 का जुर्माना लगाया गया।

अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा तथा स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 के दौरान अलार्म चैन पुलिंग की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए RPF ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के माध्यम से उल्लेखनीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे ट्रेनों की समयपालनता एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित हो सके।

स्टेशन स्तर पर अहमदाबाद, साबरमती,



मणिनगर, महेसाणा, विरामगाम एवं गांधीधाम में अलार्म चैन पुलिंग की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की

गईं। वहीं सेक्शन स्तर पर गेरतपुर-अहमदाबाद, अहमदाबाद-विरामगाम, उंझा-पालनपुर, सामाखाली-भुज तथा

अहमदाबाद-साबरमती खंडों में अधिक घटनाएँ सामने आईं, जहाँ RPF द्वारा अतिरिक्त निगरानी एवं विशेष अभियान चलाए गए।

अलार्म चैन पुलिंग के प्रमुख कारणों में गलत ट्रेन या कोच में चढ़ जाना, सामान छूट जाना अथवा सहयात्री के छूट जाने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख रूप से पाई गईं। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए RPF द्वारा यात्रियों को जागरूक करने हेतु नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं तथा रेलवे कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त आश्रम एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, अला हज्रत एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों में अलार्म चैन पुलिंग की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक पाई गईं, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेल प्रशासन एवं RPF यात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चैन का उपयोग केवल आपात स्थिति में ही करें। अनावश्यक अलार्म चैन पुलिंग में अलार्म चैन पुलिंग के कारण कई बार कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को शाम तक रुकना अथवा अगले दिन तक ठहरना पड़ता था, जिससे समय एवं संसाधनों की हानि के साथ असुविधा भी होती थी।

नई समय-सारणी के अनुसार अब ओपीडी सेवाएँ प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक निरंतर संचालित की जा रही हैं।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल के मीटरगेज सेक्शन में 23 फरवरी से जूनागढ़ चलाला के बीच चलेगी दैनिक स्पेशल ट्रेन

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर रेलवे मंडल के मीटरगेज सेक्शन में विशेष किराये पर जूनागढ़-चलाला स्टेशनों के बीच 23 फरवरी, 2026 (सोमवार) से दैनिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

जूनागढ़ से चलाला को जाने वाली दैनिक मीटरगेज स्पेशल ट्रेन जूनागढ़ स्टेशन से सुबह 10.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा यह ट्रेन दोपहर 14.10 बजे चलाला स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में चलाला से जूनागढ़ को जाने वाली दैनिक मीटरगेज स्पेशल ट्रेन चलाला से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा 17.35 बजे जूनागढ़ स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में तोरणीया, बीदवा, जुनी चावंड, बीसावदर, जेतलवड, भाडेर और धाटी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस ट्रेन का अधिक से अधिक लाभ लें।

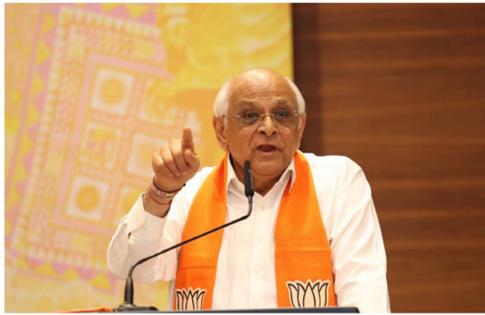


कांग्रेस पार्टी द्वारा 'एआई समिट' के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शानदार सफलता के जरिए दुनिया ने एक नए भारत का उदय देखा है।

उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के सपनों को एक नई ऊँचाई मिली है। इस पहल से स्टार्टअप और इमर्जिंग सेक्टर में युवाओं के लिए अपार अवसरों का निर्माण हुआ है। इस उपलब्धि और इस समिट से वैश्विक स्तर पर उभर रही भारत की छवि को स्वीकार न कर पाने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने की राह अपना ली है। कांग्रेस यह विरोध करने अपनी मानसिक अस्थिरता का परिचय दे रही है।



उन्होंने कहा कि जब-जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, तब उसका विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब, जब देश की युवा शक्ति के लिए विकास के नए अवसर खुले हैं, तब उन युवाओं के मन में भी शंकाएँ पैदा करने

और केवल सस्ता प्रचार प्राप्त करने के उद्देश्य से वे 'एआई समिट' का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी इस करतूत पर शर्म विकास के नए अवसर खुले हैं, तब उन युवाओं के मन में भी शंकाएँ पैदा करने

डायमंड सिटी से ग्लोबल हब तक: सूरत का निर्यात 10.55 अरब डॉलर, अमेरिका, हांगकांग और यूएई प्रमुख बाजार

जीएनएस)। गांधीनगर : भारत की निर्यात आधारित विकास रणनीति को नई गति मिल रही है और इस दिशा में गुजरात एक बार फिर अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुजरात ने 9.83 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जो देश के कुल निर्यात का 27 प्रतिशत से अधिक है। इस उपलब्धि में सूरत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 'डायमंड सिटी' के रूप में वैश्विक पहचान रखने वाले सूरत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.55 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात दर्ज कर अपनी आर्थिक क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया है।

सूरत का निर्यात मुख्य रूप से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर आधारित है। सूरत क्षेत्र में विश्व के लगभग 90 प्रतिशत हीरों का प्रसंस्करण होता है और यह कुल निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। हालांकि, सूरत की अर्थव्यवस्था अब हीरा उद्योग तक सीमित नहीं रही। मानव-निर्मित रेसे, जैविक रसायन, यांत्रिक मशीनरी तथा विविध वस्त्र



निर्माण जैसे क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं, जिससे शहर का औद्योगिक आधार और व्यापक हुआ है। वैश्विक बाजारों में भी सूरत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 32 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सूरत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है। हांगकांग (18 प्रतिशत) और

रीजनल कॉन्फ्रेंस (बीजीआरसी) दक्षिण गुजरात को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह सम्मेलन भरूच, डांग, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड जिलों को आच्छादित करेगा तथा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे उच्च-विकास क्षेत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, हाल में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के परिप्रेक्ष्य में यह सम्मेलन दक्षिण गुजरात के निर्यातकों और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

'विकसित भारत@2047' और 'विकसित गुजरात@2047' की परिकल्पना के अनुरूप, यह सम्मेलन स्थानीय एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और 'वोकल फॉर लोकल' से पहुंच लगातार बढ़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में अप्रैल 2026 में सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेट गुजरात

संयुक्त अरब अमीरात (14 प्रतिशत) भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। इसके अलावा बेल्टियम और इजराइल जैसे स्थापित बाजारों का भी सूरत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 32 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सूरत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है। हांगकांग (18 प्रतिशत) और

पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अर्जित की ₹1.72 करोड़ की रिकॉर्ड आय

जीएनएस)। यात्रियों और माल परिवहन से होने वाली आय को बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिम रेलवे गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए कई नवाचारी पहल कर रहा है। इसी दिशा में पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2025-26 के दौरान फिल्म शूटिंग से आय अर्जित करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवधि में 15 फरवरी, 2026 तक पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अब तक की सर्वाधिक लगभग 1.72 करोड़ की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से लगभग 1.64 करोड़ की आय अर्जित की थी। यह इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है तथा इस प्रकार की आय अर्जित करने में पश्चिम रेलवे को देश के अग्रणी रेलवे जनों में स्थान दिलाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों को फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, वेब सीरीज तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ



उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग को अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यार्ड तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है। पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन हाउस और फिल्म निर्माताओं को निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियाँ

प्राप्त करना आसान हो गया है। अब सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से प्रोडक्शन हाउस को केवल शूटिंग के लिए आवेदन करना होता है तथा अन्य सभी रेलवे स्वीकृतियाँ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त कर अनुमति जारी की जाती है। साथ ही, ऐसी शूटिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षा, परिचालन आवश्यकताओं और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि पहली बार भारत की सबसे आधुनिक और प्रीमियम

ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर फिल्म शूटिंग की अनुमति पश्चिम रेलवे द्वारा प्रदान की गई। इस उपलब्धि से फिल्म उद्योग को विश्वस्तरीय रेलवे अवसरचर्चा का उपयोग करने का अवसर मिला तथा पश्चिम रेलवे के प्रगतिशील और नवाचारी दृष्टिकोण को भी

प्रदर्शित किया गया। पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्थानों पर जिन फिल्मों की शूटिंग की गई, उनमें ओ रोमियो, फतेह, तेरा यार हूँ मैं, सिकंदर तथा लिजोल, पेट्रीएम, कोलगेट जैसे अनेक विज्ञापन शामिल हैं। पश्चिम रेलवे भविष्य में भी फिल्म उद्योग के साथ समन्वय को और सुदृढ़ करने, नए अवसर सृजित करने तथा गैर-किराया राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य श्रेणी (जनरल) कोचों की स्थायी वृद्धि, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम 04 सामान्य श्रेणी कोच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से होकर चलने वाली ट्रेनों की संरचना में स्थायी रूप से सामान्य श्रेणी कोचों की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा तथा भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार संशोधित कोच संरचना का विवरण निम्नानुसार है -

1. गाड़ी संख्या 12905/12906 पोरबंदर-शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार जनरल



कोचों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 किए जाएंगे। ये कोच पोरबंदर से 29 अप्रैल 2026 से तथा सिकंदराबाद से 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

3. गाड़ी संख्या 12949/12950 पोरबंदर-सांता रागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार सामान्य श्रेणी कोचों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 किए जाएंगे। ये कोच पोरबंदर से 01 मई 2026 से तथा सांता रागाछी से 03 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाते हुए सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करें।

कोचों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की जाएगी। ये कोच पोरबंदर से 28 अप्रैल 2026 से तथा सिकंदराबाद से 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

3. गाड़ी संख्या 12949/12950 पोरबंदर-सांता रागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार सामान्य श्रेणी कोचों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 किए जाएंगे। ये कोच पोरबंदर से 01 मई 2026 से तथा सांता रागाछी से 03 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाते हुए सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करें।